www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 220 नागपुर, गुरुवार, 6 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

कोर्ट ने माल्या के खिलाफ फिर जारी किया गैर जमानती वारंट

मुंबई

यहां की विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक कर्ज जालसाजी की जांच से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील हितेन वेनेगोअंकर ने कहा, अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। यह आरोप पत्र 14 जून 2017 को दायर किया गया था। अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

ईडी ने माल्या एवं आठ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया था। यह आरोप पत्र करीब 900 करोड़ रुपये के आइडीबीआइ-केएफए बैंक कर्ज मामले में मनी लांड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी के आग्रह पर अदालत ने नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनी लांड्रिंग एजेंसी ने अदालत को बताया कि माल्या ब्रिटेन में है और पूर्व में हाजिर नहीं हुआ है।

ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत 57 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया है। माल्या के अलावा इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए), यूनाइटेड ब्रेवेरीज (होल्डिंग) लिमिटेड, भंग एयरलाइंस के वरिष्ठ कर्मचारी और कार्यकारी और आइडीबीआइ बैंक आरोपी हैं। एजेंसी ने आरोप पत्र में बताया है कि किस तरह बैंक से कर्ज लिया गया और उसे विदेश में फार्मूला-1 कार रेसिंग में भेज दिया गया। इस कार रेसिंग में माल्या की फोर्स इंडिया टीम शामिल थी। एजेंसी ने बताया है कि नियमों को ताक पर रख किस तरह से 400 करोड़ रुपये विदेश भेज दिए गए।जांच में पाया गया कि माल्या, केएफए ने आइडीबीआइ बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर 860.92 करोड़ रुपये कर्ज लिया था।

असम में बाढ़ के कहर से 4 लाख लोग प्रभावित, 24 हजार लोगों ने राहत कैंप में ली शरण

इम्फाल

असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे राज्य के 13 जिलों के करीब 4 लाख लोग इसमें बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में पहुंच चुका है जिसके बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। राज्य की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से उपर पहुंच चुकी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ के कारण गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच फेरी सेवा निलंबित कर दी गई है। राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) ने 400 विद्यार्थियों को इस बाढ़ से निकाल कर नलबरी जिले में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। 3 जुलाई को लखीमपुर में बाढ़ से एक की जान चली गई। इसके अलावा करीमगंज और गोलाघाट जिले के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लगभग 24,000 लोग 108 राहत कैंपों में शरण लिए हैं। उनके बीच पानी, चावल जैसी राहत की सामग्री वितरित की गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी के गठन को लेकर याचिका दायर

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी के गठन की मांग की गई, जिसमें विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) भी शामिल हों।

सीजेआइ जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने कहा कि इस संबंध में भले ही इस तरह की कोई प्रक्रिया न हो, मगर हमें लगता है कि अब तक कि नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी रही हैं।

इस मुद्दे को संभवत: दो महीने बाद सुनवाई के लिए उठाया जाएगा। अनूप बर्नवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है तो मामला न्यायिक रूप से उठाया जा सकता है।

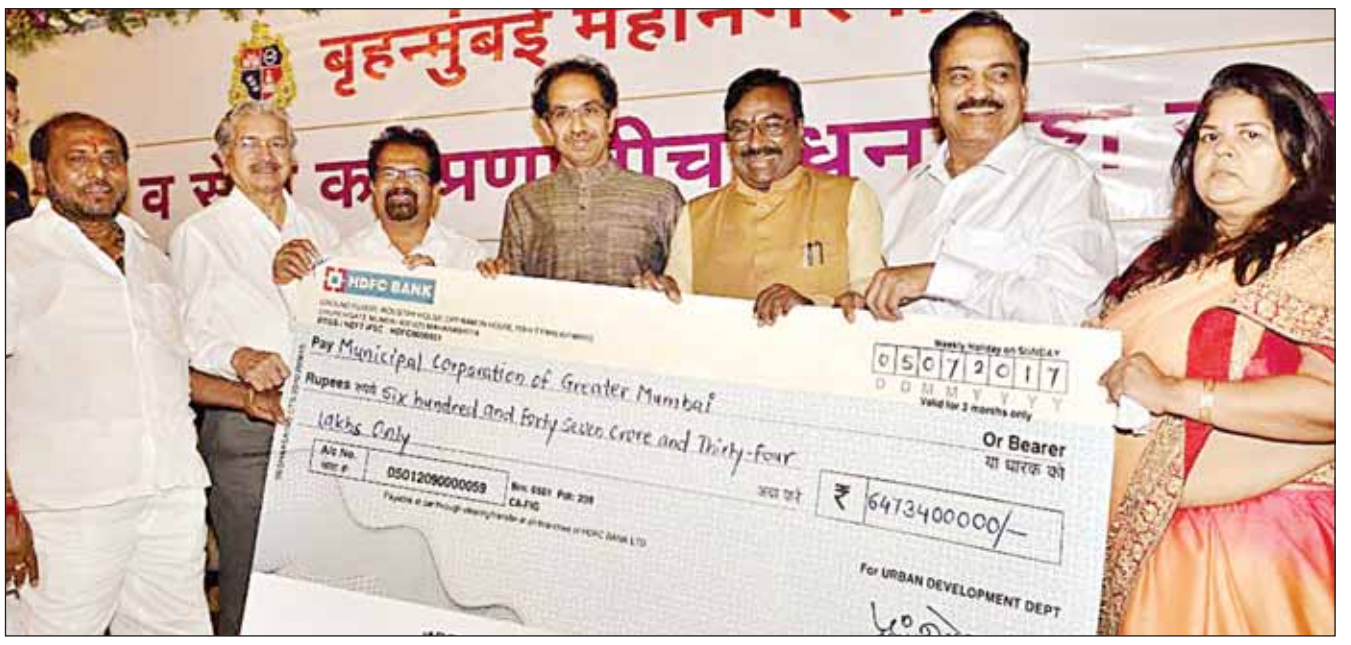

वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर व मनपा आयुक्त अजय मेहता को 647.34 करोड़ का धनादेश सौंपते हुए राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार एवं इस अवसर पर उपस्थित शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे व अन्य मान्यवर।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे भारत व इजरायल, सात समझौतों पर लगी मुहर

येरुशलम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा के दूसरे दिन भारत और इजरायल के बीच अंतरिक्ष में सहयोग और कृषि समेत सात महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को अहम बताते हुए दुनिया के सामने अपनी बातें रखीं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को उनकी पत्नी के साथ आने का न्यौता दिया, जिसे उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। भारत और इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंड एंड टेक्नॉलोजिकल इनोवेशन फंड के लिए चार सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का कोष बनाने पर सहमति जताई गई है। इसके साथ ही यूपी में गंगा की सफाई को भी इजरायल की तरफ से मदद की बात कही गई है।

कट्टरपंथी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत-इजरायल

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कट्टरवाद और आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश इसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। मोदी ने कहा कि इजरायल आविष्कारों का गढ़ है। ऐसे में यहां से भारत को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में इजरायली पर्यटकों की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है।

नई ऊंचाई पर ले जाएंगे भारत-इजरायल की दोस्ती

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल की इस दोस्ती को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत और इजरायल के आतंकवाद से ग्रस्त होने की वजह उसकी भौगोलिक दशा है। मोदी ने कहा कि इजरायल जल संरक्षण और कृषि प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में काफी आगे है। साझा प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की है कि किस तरह हमारे सहयोग से वैश्विक शांति और स्थिरता को मदद मिल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही हमारे रास्ते अलग रहे हों, लेकिन लोकतंत्र में हम दोनों का हमेशा से विश्वास रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में इजरायल के लोगों ने सफलता पायी है उसकी भारत प्रशंसा करता है।

भारत-इजरायल के बीच सात महत्वपूर्ण समझौते

- भारत और इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंड एंड टेक्नॉलोजिकल इनोवेशन फंड
- भारत में पानी का संरक्षण
- भारत में जल प्रबंधन
- इजरायल-भारत विकास सहयोग
- एटोमिक क्लॉक्स समन्वय
- जीओ-लियो ऑप्टिकल लिंक के क्षेत्र में सहयोग
- छोटे सैटेलाइट को लेकर समझौते

महाराष्ट्र सरकार लागू करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति

नगरपालिका क्षेत्र में भी होगा क्रियान्वयन - मुख्यमंत्री

मुंबई

उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां आसानी से मिल सकें इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति लागू कर रही है । अब महानगरपालिका क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में भी इस नीति को लागू किया जायेगा।

महाराष्ट्र सरकार और क्रेडाई (सीआरईडीएआइ), एम सी एच आय तथा मीडिया पार्टनर (ज़ी-2) के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागार में आयोजित गृहनिर्माण- नयी दिशा विषय पर आधारित गोष्ठी में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस बोल रहे थे ।

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर परिसंवाद आयोजित करने के लिए क्रेडाई का अभिनंदन किया । उन्होंने कहा कि गृहनिर्माण क्षेत्र में तंत्रज्ञान और नीति में परिवर्तन हो रहे हैं । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस संगोष्ठी में विविध विषयों पर होने वाली चर्चा के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद सरकार को सूचित करने के लिए इम्पावरमेंट कमेटी स्थापित किये जाने की घोषणाा की। इस समिति में नगर विकास विभाग के दोनों सचिव, गृहनिर्माण विभाग के सचिव, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, क्रेडाई के प्रतिनिधि का समावेश होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नगरपालिका क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना आसान हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम एम आर क्षेत्र में उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रमाणीकरण होना चाहिए ।

रेरा कानून व डिजिटल प्लेटफार्म के कारण उद्यमियों को साफ सुथरे ढंग से उद्योग करने का अवसर मिला है । रियायती दर पर गृह निर्माण कार्यक्रम के चलते रोजगार मिलेगा व सबको घर मिल सकेंगे, इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। सब मिलकर समाज और राज्य के हित में उत्तम कार्य करें, ऐसा आव्हान मुख्यमंत्री ने किया।

उदय निरगुडकर ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की केंद्र सरकार की नीति है । इसे पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए । क्रेडाई के अध्यक्ष धर्मेश जैन ने परिचर्चा आयोजित करने के पीछे की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि गृहनिर्माण क्षेत्र राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा।

उक्त आयोजित परिचर्चा में मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु संजय देशमुख के अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा अनेक व्यवसायी भी प्रमुखता से उपस्थित थे।

राज्य में तनाव पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा - पर्रिकर

पणजी

दक्षिण-गोवा में मंदिरों, गिरजाघरों सहित धार्मिक प्रतीकों के अपमान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य में तनाव पैदा करने के लिए कुछ लोगों क द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पर्रिकर ने कहा, राज्य में किसी प्रकार के तनाव पैदा करने की कोशिश में कुछ समूहों द्वारा विषेश प्रयास किये जा रहे हैं, जिन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पकड़े जाने पर उन्हें कठोर दंड का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं - राहुल गांधी

नई दिल्ली

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को हाल ही में अमेरिका का दौरा कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया। राहुल गांधी ने उन अखबारों का हवाला दिया, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष एच1 वीजा का मुद्दा नहीं उठाया था।

इसके अलावा किस तरह विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अमेरिका में महत्वपूर्ण नहीं दिखाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर शब्द के इस्तेमाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा, जिसमें राज्य विभाग के नोटिफिकेशन में पाकिस्तान के सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी करार दिया गया था।

भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर इस स्थिति की तरफ इशारा करता है कि सैयद सलाहुद्दीन को भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंक के लिए शामिल किया गया था।

इसी तरह का शब्द भारत में सीमापार आतंकवाद के संबंध में राज्यों के रिपोर्टों में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वर्ष 2010-2013 की अवधि में आतंकवादी हमला किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागेले ने एक बयान में कहा, सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।

पश्चिम बंगाल में हिंसा, केंद्र ने ममता सरकार से की रिपोर्ट तलब

बीएसएफ के 400 जवानों को तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना किया

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को संज्ञान में लेते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने हिंसा के कारण और उससे उपजे हालात के तथ्य की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से टेलीफोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली, वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर ममता बनर्जी की ओर लगाए गए आरोपों पर गृह मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंसा भड़कने के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांग ली गई थी। राज्य सरकार को भेजे लिखित संदेश में हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के लिये किये गये उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। हिंसा फैलने के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग थी। बीएसएफ के 400 जवानों को तत्काल घटनास्थल की रवाना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की मांग नहीं की गई है, लेकिन ऐसी मांग पर रिपोर्ट आने के बाद ही विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की समुचित तैनाती नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बातचीत में राज्यपाल की ओर से किये कथित दुर्व्यहार के बारे में राजनाथ सिंह को जानकारी दी, लेकिन गृहमंत्री की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल और राज्य सरकार की ओर विस्तृत रिपोर्ट आ जाने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है।

हत्या की वारदातों से भारत की साख पर लगा सवालिया निशान - यशवंत सिन्हा

नई दिल्ली

भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं से जो माहौल बना है वह भारत के लिए अच्छा नहीं है। इससे विदेशी मुल्कों में नकारात्मक संदेश जा रहा है। अहम बात है यह कि इस तरह के माहौल में विदेशी निवेशक पीछे हटने लग जाते हैं।

सिन्हा का कहना है कि 2012 में वह जर्मनी में एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान दे रहे थे, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म पर उनकी क्या राय है। उनका कहना है कि लोग मानते हैं कि अगर भीड़ के हाथ में न्याय व्यवस्था है तो फिर सरकार क्या कर रही है। उनका कहना है कि इस तरह की वारदातों से सबसे बड़ा झटका अर्थव्यवस्था को लगता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के ताजा बयान पर उनका कहना था कि वह बेवजह ही बहस में नहीं पड़ना चाहते। उल्लेखनीय है कि शाह ने पिछले दिनों कहा था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में भीड़ द्वारा हत्या करने की वारदातें ज्यादा थीं। सिन्हा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए। उधर, इंडिया स्पेंड संस्था ने अपने आंकड़ों से सरकार को आइना दिखाया है। संस्था का दावा है कि 2010 के बाद से इस तरह की 63 वारदातें हुईं, जिसमें 61 भाजपा के कार्यकाल में हुईं। इस तरह के हमलों में जो 28 लोग मारे गए उनमें 24 मुस्लिम थे। 2017 के पहले छह माह के दौरान गाय व गोमांस को लेकर 20 मामले ऐसे थे, जिसमें भीड़ ने हमला किया।